ing in view the importance of such meetings. The question of further strengthening of staff in our mission to W.T.O. in Geneva will be considered on merits, gcrc 4Mi< 'fif fart aftr faraft fewr eKi

सुपर बाजार में वित्त मंत्री और ब्रिकी विभाग का मध्यवर्गीय मूल्यांकन

1056. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाजार के वित्त और ब्रिकी विभागों का कोई मध्यावधि मूल्यांकन किया है,

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले,

(ग) क्या इस अवधि के दौरान उक्त संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायी हैं,

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं,

(ड.) क्या सुपर बाजार के महाप्रबंधक और कर्मचारियों के बीच तालमेल का अभाव है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (ग) सुपर बाजार एक स्वायत्तशासी सहकारी सोसायटी है । इसका अपने व्यापार के नियोजन तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए स्वंय का एक प्रबंध मंडल है ।तथापि, भारत सरकार जनहित में इसके कार्य की समय-समय पर समीक्षा करती है तथा सुपर बाजार के लेखा परीक्षित लेखाओं को हर वर्ष संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखती है ।

गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार के लक्ष्य तथा उपलब्धियां जैसी की सुपर बाजार द्वारा भेजी गई है, निम्नवत है:-

(लाख रू. में)

	1992-93	1993-94	1995-95
अनुमानित बिक्री	12333.00	13535.00	14544.00
वास्तविक बिक्री	10303.98	11520.34	13015.23
अनुमानित शुद्ध लाभ	16.90	15.73	24.75
वास्तविक लाभ	10.83	41.65	22.11

(घ) भारत सरकार सुपर बाजार को जनहित में विस्तार विविधीकरण तथा नवीकरण कार्यक्रम के लिए कुछ वित्तीय सहायता देती है ।

(ड.) जी नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता है ।

गुजरात में कोयले का दोहन

1057. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में कोयले के दोहन के लिए केन्द्रीय सरकार को कई प्रस्ताव भेजे हैं,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन प्रस्तावों का विचार या उनका अध्ययन किया है,

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान गुजरात में कोयले के दोहन के लिए किसी क्षेत्र के बारे में विचार किया जा रहा है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ड.) गुजरात में प्रति वर्ष जिला-वार कुल कितने कोयले की मांग है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई है,

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) गुजरात राज्य मे कोयले के भंडार पाये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ड.) से (छ) कोयले की मांग का मूल्यांकन समग्र रूप से देश के बिना क्षेत्र-वार किया जाता है और अलग से जिला-वार मांग के अनुमानों को नहीं लगाया जाना है । को.ई.लि. स्त्रोतों से वर्ष 1995-96 (दिसम्बर, 1995 तक) के दौरान गुजरात राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयलो की आपूर्ति 11.37 मिलियन टन (अनंतिम) की गई थी । रेल या सड़क द्वारा उद्योगों को प्रस्तुत किए गए संपूर्ण कार्यक्रम को पूरा किये जाने का कोल इंडिया लिए प्रयास कर रही है । रेल द्वारा संकलन में यदि कमी होती है तो ऐसी स्थिति में उनके उपयोग न किये गये प्रयोजनों/योजनाओं के एवज में सभी उपभोक्ताओं को यह अवसर दिया जाता है कि वे अपने आर्डर द्वारा यह अवसर दिया जाता है कि वे अपने आर्डर द्वारा करा सके । इसके अतिरिक्त कई

कोलियरियों से प्राप्त कोयले को उदारीकृत बिक्री योजना के तहत पेशकश की जाती है । उपभोक्ताओं को अपने आर्डरों की बुकिंग कराने का अवसर क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक अहमदाबाद के माध्यम से भी प्रदान किए गए हैं ।

Energy efficient label products

1058. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in many countries it is mandatory for the manufacturers of home appliances to affix energy efficient label on their products;

(b) whether it is also a fact that this practice has not yet been adopted by the local manufacturers of such products;

(c) whether Government propose to direct the manufacturers of such appliances to have such a label on their products; and

(d) if so, by when and if not reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) As per the information available, energy labelling is being done on some domestic appliances in some countries.

(b) The concept of energy labelling on home appliances is not widely prevalent in India.

(c) No such proposal is presently under consideration.

(d) The process of identification of criteria for energy efficiency through standards has been initiated.

विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सर्वेक्षण

1059. **श्री भागमणि** :

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिविल निर्माण, कृषि, ईंटों के भट्ठों तथा स्टोन वर्क्स सेक्टर और होटलों में कार्यरत व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार एंव उनके कल्याण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्री (श्री जी.वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) श्रम ब्यूरो, जो श्रम मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, ने भवन और निर्माण उद्योग, ईंट भट्ठा उद्योग तथा पत्थर खदान उद्योग में लगे कर्मकारों की कामकाजी और रहन-सहन की परिस्थितियों के कुछ सर्वेक्षण करवाए हैं । ब्यूरो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सामान्य रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों के साथ पंचवर्षीय आधार पर आयोजित ग्रामीण श्रम जांचों के संबंध में रिपोर्टें भी प्रकाशित करता है । कुछ सर्वेक्षणों के मुख्य-मुख्य निष्कर्ष सलंग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

भवन निर्माण, उद्योग ईंट भट्ठा उद्योग तथा पत्थर खदान उद्योग में लगे कर्मकारो की परिस्थितियों के संबधं में कराए गए सर्वेक्षणों के निष्कर्ष

I. दिल्ली में भवन और निर्माण उद्योग का सर्वेक्षण (1997-98)

सर्वेक्षण से पता चलता है कि महिला कर्मकार कुल श्रम बल का लगभग 20% थी और अकुशल कार्यों में लगी थी । बालकों का नियोजन भी विद्यमान पाया गया था । दैनिक मजदूरी की अदायगी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार की जाती थी । कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अंतर्गत अदायगी को छोड़कर कुछ सामाजिक सुरक्षा लाभ मुहैया नहीं करवाए जा रहे थे । कुशल कर्मकारों का लगभग 38% और अकुशल कर्मकारों का लगभग 56.7% ऋण ग्रस्त पाए गए ।

II. हरियाणा में ईंट-भट्ठा उद्योग का सर्वेक्षण (1982)

सर्वेक्षण से पता चलता है कि उत्पादन प्रयोजनों के लिए केवल पुरूष नियोजित थे । इनमें से 97% कर्मकार